P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-4* July- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

भारत में आपदा प्रबन्धन

अनुज सिंह
शोध छात्र,
भूगोल विभाग,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर, उ0प्र0

सारांश

आधुनिक प्रगति एवं व्यक्तिगत हितों के कारण प्राकृतिक आपदाओं का भारत के साथ–साथ वैश्विक स्तर पर प्रसार हो रहा है। यह तत्कालीन या लम्बे समय से चली आ रही परिस्थितियों का परिणाम हो सकता है। इससे मनुष्य का आम सामाजिक, परम्परागत और आर्थिक जीवन अस्त–व्यस्त हो जाता है, जिसके कारण मानव समाज को विषम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपदा समाज की कार्यप्रणाली का एक गम्भीर, विघटनकारी एवं विध्वंसात्मक नुकसान है जो व्यापक तौर पर मनुष्य, पदार्थ तथा पर्यावरण को क्षति पहुँचाता है। यह समाज तथा प्राकृतिक संसाधनों दोनों को विनष्ट एवं प्रभावित करता है। अतः आपदा प्रबन्ध हेतु जन–जागरूकता अभियान के साथ–साथ न केवल व्यापक कार्ययोजना बनाए जाने की आवश्यकता है बल्कि उस कार्य योजना के समय–समय पर नवीनीकरण की महती आवश्यकत है। इस दिशा में शिक्षण संस्थाएँ एवं मीडिया अपनी उपयोगी भूमिका निभा सकती है। अतः प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में आपदा प्रबन्धन की संरचना, रणनीति एवं रोजगार के अवसर का अध्ययन किया गया।

मुख्य शब्द : प्राकृतिक, परिस्थितियों, सामाजिक, परम्परागत, विघटनकारी, विध्वंसात्मक।

प्रस्तावना

आपदा का अर्थ है, अचानक होने वाली एक विध्वंसकारी घटना जो मानवीय भौतिक, पर्यावरणीय एवं सामाजिक कार्यकरण को व्यापक तौर पर प्रभावित करती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में के अनुसार आपदा प्रबनधन से तात्पर्य 'आपदा किसी समुदाय या समाज के कामकाज में एक गंभीर व्यवधान है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर मानवीय आर्थिक और पर्यावरणीय क्षति होती है, जो उस समुदाय या समाज द्वारा अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए इससे मुकाबला करने की क्षमता से परे है। सावधानी से बनायी गयी योजना, तत्परता और शमन के उपायों के प्रयोग द्वारा संकटों से बचा जा सकता है।' भारत के पास आपदाओं के जोखिम को परखने की अच्छी वैज्ञानिक और पारंपरिक जानकारियां हैं जिससे हम प्राकृतिक ओर मानवजनित प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं, लेकिन इन्हें सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्यक्रमों, गतिविधियों और परियोजनाओं की डिजाइनिंग और कार्यान्वयन में शामिल नहीं किया जाता। इसके परिणामस्वरूप आपदा के जोखिम को कम करने से संबंधित परियोजनाओं का अधिक लाभ नहीं मिलता। कई बार तो इन परियोजनाओं से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपदाओं के नए जोखिम खड़े हो जाते हैं या मौजूदा जोखिम और प्रचंड हो जाते हैं।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोध प्रपत्र के लिए निम्न साहित्यों का अध्ययन किया गया है– दृष्टि पब्लिकेशन–(2017) : पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, सविन्द्र सिंह (2014): पर्यावरण भूगोल, सविन्द्र सिंह (2014): आपदा प्रबन्धन, भूगोल और आप मई (2018), योजना पत्रिका जनवरी (2017), रमा शर्मा एवं एम0के0 मिश्रा (2009): पर्यावरण शिक्षण, डॉ0 आलोक कुमार कश्यप एवं डॉ0 सुरेन्द्र पाल (2014): पर्यावरण एवं समाज।

अध्ययन का उद्देश्य

1. भारत में उच्च जोखिम वाले, आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन करना।
2. भारत में आपदा प्रबंधन की रणनीति, संस्थागत संरचना एवं रोजगार के अवसर का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक स्त्रोतों पर आधारित है जिसके अन्तर्गत सरकारी प्रपत्रों, शोध पत्रिकाओं, पुस्तकों का अध्ययन किया गया है, मानचित्र एवं रेखाचित्र की भी सहायता ली गयी है।

भारत में उच्च जोखिम वाले, आपदा से प्रभावित क्षेत्र

भारत सरकार ने सन् 1997 में राष्ट्रीय सुभेधता एटलस का प्रकाशन किया जिसमें भारत के प्रकोप एवं आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों को दर्शाया गया था। भारत के 'गृह मंत्रालय' तथा 'संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम' ने मिलकर देश के 125 जिलों के 'सर्वाधिक प्रकोप–प्रभावित क्षेत्रों' की सूची तैयार की है। इस सूची में देश के चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, मुम्बई, कोलकत्ता, चेन्नई) तथा 8 प्रान्तों की राजधानी नगरों को भी सम्मिलित किया गया है–

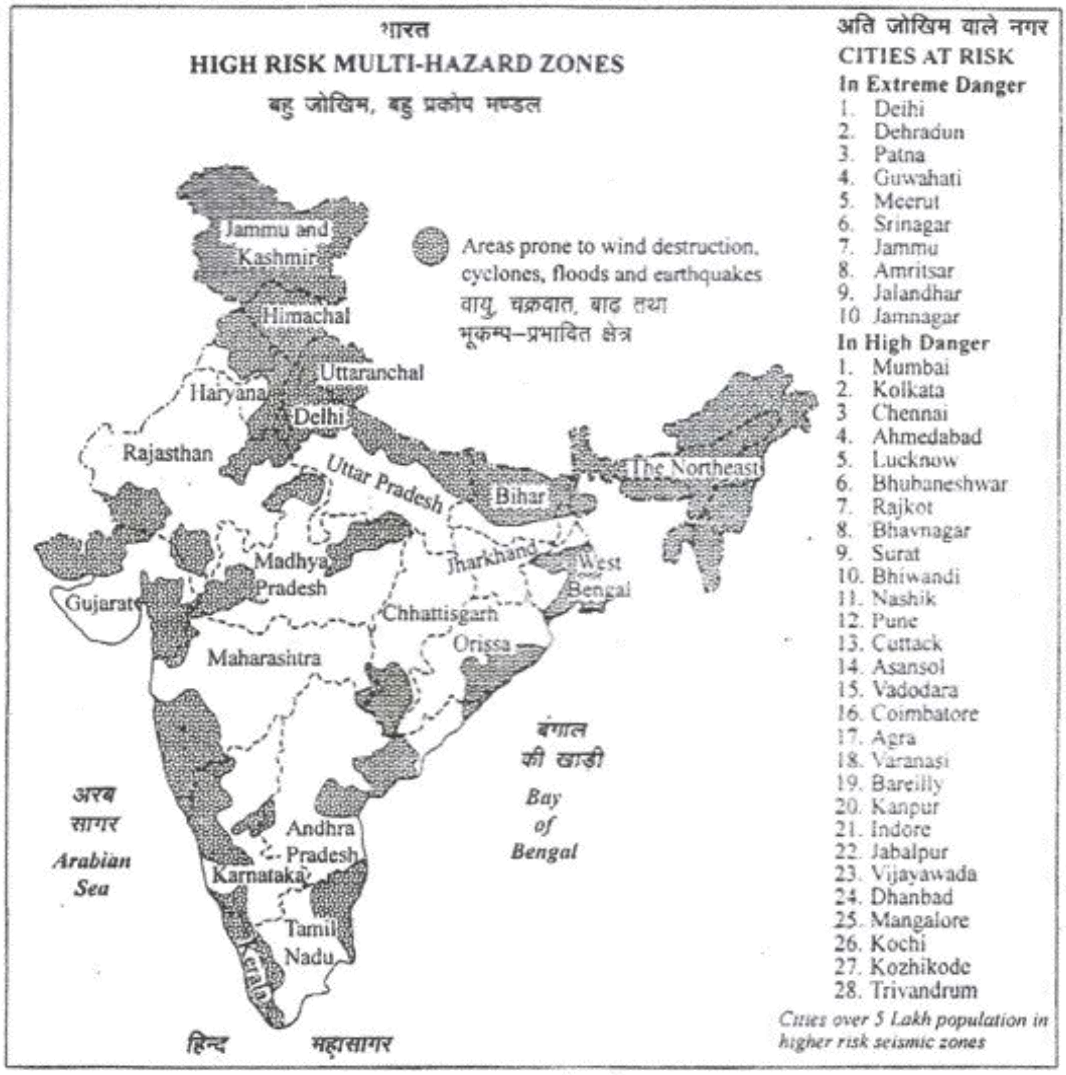

(भारत के उच्च जोखिम वाले बहु–प्रकोप मण्डल स्रोतः राजेश रामचन्द्रन, आउटबुक 2005)

भारत में आपदा प्रबंधन की संस्थागत संरचना

भारत में आपदा की चुनौतियों से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने 2005 में आपदा प्रबन्धन अधिनियम बनाया जिसके अन्तर्गत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एनडीएमए) का गठन किया गया है जिसमें उपाध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्य सम्मिलित हैं। एनडीएमए मे गृह, वित्त और कृषि विभाग के मंत्री तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष बैठक में स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं जिससे निर्णयों में तालमेल बनाया जा सके और आपदा प्रबन्धन को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकें। इसी तरह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबनन प्राधिकरण का गठन किया गया है।

भारत में आपदा प्रबन्ध संस्थागत संरचना

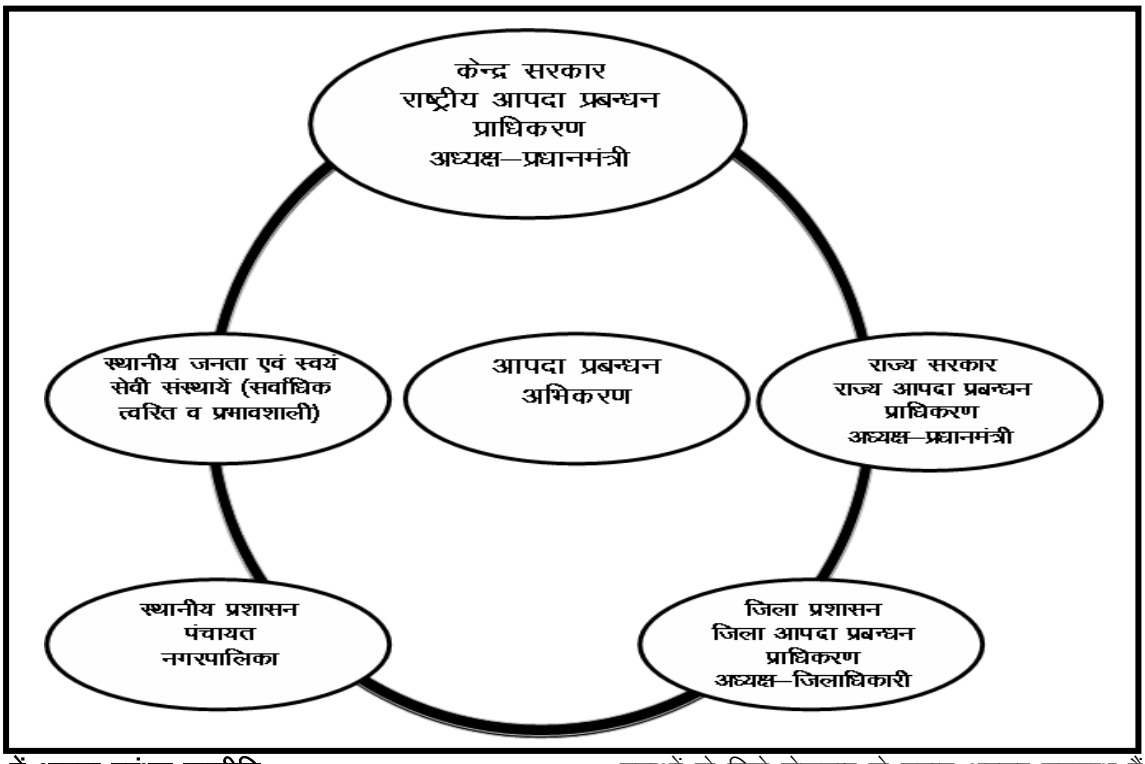

भारत में आपदा प्रबंधन रणनीति

किसी भी आपदा के लिए, आपदा प्रबन्धन को मुख्यतः चार चरणों में बांटा जाता है। प्रथम चरण होता है आपदा की रोकथाम। इस सिलसिले में प्रयास होता है कि प्रत्याशित आपदा की पूर्व सूचना से क्षेत्र को जल्द से जल्द सचेत किया जाए जिससे जन हानि की कम से कम किया जा सके। दूसरा चरण होता है आपदाओं से निपटने की तैयारी। इस चरण में दुर्घटना घटते ही त्वरित सूचना सभी संबंधित विभागों तक पहुंचाई जाती है, आपातकालिक स्थिति में प्रतिक्रिया का समय कम से कम हो इसलिए आपदा से निपटने के साधनों का पर्याप्त भंडारण किया जाता है। तीसरा चरण होता है प्रभावित क्षेत्र में राहत सामग्री पहुंचाना, जैसे भोजन, पानी, दवाइयां, कपड़े, कम्बल इत्यादि अंतिम चरण होता है प्रभावित क्षेत्र का पुनर्निर्माण और विस्थापितों का पुनर्वास।

भारत में आपदा प्रबन्धन में रोजगार के अवसर

भारत में आपदा प्रबन्धन पर सरकार के व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के कारण रोजगार की सम्भावनाएं भी बढ़ रही है जिसके लिए आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण के विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा आपदा प्रबन्धन में स्नाकोत्तर डिप्लोमा, मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई और सिक्किम मणिपाल स्वास्थ्य चिकित्सा और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित आपदा प्रबन्धन में एक वर्षीय स्नाकोत्तर डिप्लोम, राष्ट्रीय सिविल डिफेंस काले,ज नागपुर द्वारा संचालित परमाणु, जैविक और रासायनिक दुर्घटनाओं में प्रबन्धन प्रशिक्षण प्रमुख हैं। जिसमें वर्तमान समय में युवाओं के लिये रोजगार के तमाम अवसर उपलब्ध हैं।

निष्कर्ष

हम आपदा को रोक भले नहीं सकते हैं परन्तु सक्षम तैयारी एवं प्रबन्धन से उसके दुष्प्रभाव को कम अवश्य कर सकते हैं। इसके लिए सरका को तात्कालिक व दीर्घकालिक रणनीति बनानी होगी तथा बजट की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि आपदा न्यूनीकरण के लिए खर्च किये गये बजट से मानवीय व आर्थिक क्षति को कम करने के साथ–साथ विकास की विभिन्न परियोजनाओं को सफल बनाने में भी सहयोग मिलेगा।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *सिंह, सविन्द्र 2010 : पर्यावरण भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद।*
2. *एन0सी0ई0आर0टी0 2006 : भारत भौतिक पर्यावरण, नई दिल्ली।*
3. *कार्टर, डब्लू, निक (1991) : डिजास्टर मैनेजमेंट : ए डिजास्टर मैनेजर्स हैण्ड बुक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला।*
4. *थामस बाबू, 1993 'डिजास्टर रेस्पॉन्स ए हैंड बुक फार इमरजेंसी' चर्चस ऑक्सिलरी फार सोशल ऐक्शनः नई दिल्ली।*
5. *योजना पत्रिका, जनवरी (2017): पृ0सं0 15,33,37,39*
6. *भूगोल और आप मई (2018) पृ0सं0 6,9,10*
7. *प्रकाश, इन्दु, (1994) 'डिजास्टर मैनेजमेंट', राष्ट्र प्रहरी प्रकाशन, गाजियाबाद।*